हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड बनाम एम/एस ह्यूमन राइस मिल और अन्य

1755

(अमन चौधरी, जे.)

अमन चौधरी से पहले, जे.

हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड-अपीलार्थी

बनाम

मेसर्स ह्यूमन राइस मिल और एक और-उत्तरदाता

2022 का सी. आर. ए.-ए. एस. संख्या 338

07 नवंबर, 2022

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-चेक का अपमान-15 दिनों के लिए जारी कानूनी नोटिस-15 दिनों की समाप्ति से एक दिन पहले शिकायत विफल हो गई-आयोजित, शिकायत पूर्व-परिपक्व है, इसलिए बनाए रखने योग्य नहीं है, खारिज कर दी गई। अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय ने शिकायत को उचित रूप से विचारणीय नहीं माना था, क्योंकि यह पूर्व-परिपक्व होने के कारण, अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान की एक महत्वपूर्ण शर्त को निर्विवाद रूप से पूरा नहीं किया गया था।

(पैरा 29) पवन गिरधर और मानव बजाज, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से। प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता परमिंदर सिंह

फैक्ट मैट्रिक्स (2) संक्षेप में कहें तो, शिकायतकर्ता-अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत में किए गए दावे थे कि पक्षों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, प्रत्यर्थियों को सीमा शुल्क मिलिंग के लिए 47322 कुंतल और 80 किलोग्राम धान की आपूर्ति की गई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि शेलर से इसे उठाने पर, इसमें 6738 क्यूएनटी की कमी पाई गई थी। 2 किलोग्राम, कुछ तिरपाल और लकड़ी के डिब्बों के साथ। कुल नुकसान की गणना Rs.78,00,800/- तक की गई। शिकायत में आगे यह कहा गया कि उसी मौजूदा आंशिक दायित्व के निर्वहन में प्रतिवादी ने 1756 में एक चेक जारी किया।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

(3) अपनी शिकायत को साबित करने के लिए, शिकायतकर्ता ने राजवीर सिंह डी. एम., हाफेड, यमुनानगर से सी. डब्ल्यू. 1, धर्मपाल से सी. डब्ल्यू. 2 के रूप में पूछताछ की और कानूनी नोटिस और सुरेश कुमार, क्लर्क, एस. बी. आई. को सी. डब्ल्यू. 3 के रूप में पेश करने के बारे में बताया और अपने साक्ष्य में चेक रिटर्न रजिस्टर की प्रमाणित प्रति Ex.CW3/A, खाते का विवरण Ex.CW3/B और उसके प्राधिकरण पत्र को Ex.CW3/C के रूप में साबित किया। (4) शिकायतकर्ता के साक्ष्य को बंद करने पर, आरोपी का बयान धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि शिकायतकर्ता द्वारा उससे 3 लाख रुपये के एफ. डी. आर. के साथ सुरक्षा के रूप में एक दिनांकित खाली चेक पहले ही ले लिया गया था, जब समझौता किया गया था और शिकायतकर्ता द्वारा उक्त चेक का दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि शिकायतकर्ता के प्रति कोई बकाया राशि नहीं थी। बचाव में अभियुक्त ने यमुनानगर के उपायुक्त के कार्यालय में डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने डी. डब्ल्यू. 11 को डी. डब्ल्यू. 1 साबित किया, हाफेड के प्रतिबंध अधिकारी ऋषि राज शर्मा ने डी. डब्ल्यू. 2 के रूप में, जिन्होंने अपने साक्ष्य में साबित किया, डी. डब्ल्यू. 3 के रूप में हाफेड, यमुनानगर के कार्यालय के सहायक अशोक गुप्ता, जिन्होंने अपने साक्ष्य दस्तावेजों में अभियुक्त उत्तरदाताओं द्वारा जवाबी दावा दायर करने के संबंध में डी. डब्ल्यू. 2 और डी. 8 के रूप में साबित किया, जिसके लिए मध्यस्थता की गई। डी. डब्ल्यू. 4 के रूप में अधिवक्ता जोरा सिंह, जिन्होंने शिकायतकर्ता की ओर से अभियुक्तों को भेजे गए अपने आईडी 12 के साक्ष्य नोटिस में साबित किया-प्रतिवादी डी. डब्ल्यू. 5 के रूप में अधिवक्ता डी. एस. पनेजटा, डी. डब्ल्यू. 6 के रूप में शमशेर सिंह कंबोज (अनजाने में डी. डब्ल्यू. 3 के रूप में लिखा गया), जिन्होंने साबित किया कि उन्होंने दस्तावेजों को Ex.D25 और Ex.D26 प्रमाणित किया था, और डी. डब्ल्यू. 7 के रूप में फोरेंसिक दस्तावेज़ विशेषज्ञ देवेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सबूत में अपनी रिपोर्ट Ex.DW7/A के रूप में प्रस्तुत की। फोटोग्राफिक चार्ट Ex.DW7/B से Ex.DW7/G के रूप में कि ज्ञापन पर तारीख बदल दी गई थी और हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संगठन लिमिटेड बनाम एम/एस मानव संसाधन निगम और अन्य

1757

(अमन चौधरी, जे.)

प्रस्तुतियाँ (7) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने शिकायतकर्ता के नेतृत्व में साक्ष्य की ठीक से सराहना किए बिना शिकायत को खारिज करने और आरोपी को बरी करने में गंभीर त्रुटि की थी। शिकायत को खारिज करने का एक आधार यह था कि 14वें दिन दर्ज की गई शिकायत समय से पहले की गई थी। इस संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह आधार गलत था क्योंकि एक बार उसी दिन शिकायत का संज्ञान लेने के बाद, शिकायत को पूर्व-परिपक्व नहीं माना जा सकता था। विद्वत विचारण न्यायालय ने इस आधार पर शिकायत को खारिज करते हुए एक अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान न्यायालय ने गलत तरीके से माना था कि शिकायत किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की गई थी। इस संबंध में, उनका निवेदन है कि निगम के एक अधिकारी होने के नाते, जिला प्रबंधक द्वारा अपने हाथों से दायर की गई शिकायत के लिए आगे किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा प्रत्यर्थियों को बरी करने का आधार यह था कि प्रत्यर्थियों को आपूर्ति की गई धान की मात्रा के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस संदर्भ में, वह प्रस्तुत करता है कि समझौते के संदर्भ में, आपूर्ति की गई धान की कुल मात्रा 47322.80 क्विंटाल थी, लेकिन प्रतिवादी उसे वापस करने में विफल रहे, जिस पर, शिकायतकर्ता को शेलर से उसे उठाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद, यह 6738.2 क्विंटाल से कम पाया गया। इसलिए, लेखा पुस्तिका आदि प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, और इससे बरी होने का आधार नहीं बन सकता था। उपरोक्त के अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि निगम के गवाहों की गवाही में निगम के रिकॉर्ड में कस्टम मिलिंग के लिए उत्तरदाताओं को धान की आपूर्ति का एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया था। निचली अदालत ने यह भी पाया था कि जिस चेक का अनादर किया गया था, उस पर कोई तारीख नहीं थी। इस संबंध में, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि हालाँकि शिकायत 1758 की फोटोकॉपी के साथ थी

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

इंद्र कुमार पटोदिया और एक अन्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य 1 का मामला।

(11) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि 1 2012 (13) एस. सी. सी. 1 हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड बनाम एम./एस. ह्यूमन राइस मिल और अन्य

1759

(अमन चौधरी, जे.)

(13) खंडन में शिकायतकर्ता-अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि समझौते के खंड 12 (II) को देखते हुए किसी भी परिस्थिति में, एक दिनांकित और अपूर्ण चेक को प्रतिभूति के रूप में नहीं दिया गया होगा, जो प्रत्येक टन मिलिंग के लिए Rs.25,00,000/- की राशि निर्दिष्ट करता है। (14) पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों को विस्तार से सुना।

1760

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

(18) इसी तरह, हाफेड के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी, डी. डब्ल्यू. 2, ऋषि राज शर्मा ने अपने बयान में पक्षकारों के बीच लेन-देन से संबंधित लेखा विवरण को डी-10 से डी-22 के रूप में साबित किया था। (19) हाफेड के कार्यालय से डी. डब्ल्यू. 3, सहायक अशोक गुप्ता ने डी. 1 से डी. 24 तक साबित किया, जिससे उन्होंने इस तथ्य को साबित कर दिया कि काउंटर हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाम एम./एस. ह्यूमन राइस मिल और अन्य का दावा करता है।

1761

(अमन चौधरी, जे.)

(20) डी. डब्ल्यू. 4 जोरा सिंह अधिवक्ता ने अपने साक्ष्य में, शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को भेजे गए 17.8.2010, Ex.D4 दिनांकित नोटिस को साबित किया था। (21) फोरेंसिक विशेषज्ञ, डी. डब्ल्यू. 7 देवेंद्र प्रसाद ने अपनी राय दी, Ex.DW-7/A, जो इस प्रकार हैः -

(I) मूल चेक Ex.C-1 (3.2.13 पर प्रदर्शित) पर दिखाई देने वाली '2-6-2010' पढ़ने की तारीख मामले की फाइल पर इस चेक की दो फोटोस्टेट प्रतियों की प्रदर्शनी के बाद लिखी गई है, जो मूल चेक में सामग्री परिवर्तन के बराबर है, यानी मूल चेक Ex.C-1 (3.2.13 पर प्रदर्शित) अपनी वर्तमान स्थिति में एक परिवर्तित दस्तावेज है क्योंकि इसकी फोटोस्टेट प्रतियां Ex.C-1 (3.11.2010 पर प्रदर्शित) और Ex.D-1 (23.10.13 पर प्रदर्शित) केस फाइल। (II) मेमो एक्स के लाल घेरे हुए भाग चिह्न 'बी' में दिखाई देने वाली मूल तिथि। सी-2 को '1/10 यू' के रूप में लिखा गया था, जिसे बाद में जोड़कर '6/10 यू' पढ़ने की वर्तमान तिथि में परिवर्तित और परिवर्तित कर दिया गया है। ”

(22) निचली अदालत ने शिकायत को समयपूर्व होने के कारण खारिज करते हुए कहा हैः -

“21. वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को कानूनी नोटिस पंजीकृत पत्र के माध्यम से 20-10-2010 पर भेजा गया था, जिसकी डाक रसीदें दिनांकित 21-10-2010 हैं जो Ex.C4 और Ex.C5 हैं। भले ही शिकायतकर्ता का तर्क (हालांकि साबित नहीं हुआ) इस प्रभाव के लिए सही माना जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को कानूनी नोटिस हाथ से भेजा गया था, फिर भी शिकायतकर्ता वर्तमान शिकायत दर्ज करने से पहले 15 दिनों यानी 4-आई. डी. 2 तक इंतजार करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत था। हालाँकि हाथ में शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा 3-11-2010 पर दायर की गई थी और इस अदालत के विद्वान पूर्ववर्ती ने 3-11-2010 पर ही शिकायत और प्रारंभिक साक्ष्य 1762 पर संज्ञान लिया।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

जैसा कि नरसिंह दास तपडिया (ऊपर) एक मामला है जहाँ यद्यपि दाखिल करना समय से पहले हुआ था, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करके और बाद की तारीख को समन आदेश पारित करके संज्ञान लिया गया था जब मामला अब समय से पहले का मामला नहीं था। इन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल समय से पहले शिकायत दर्ज करने से शिकायत को खारिज करने का अधिकार नहीं है और मजिस्ट्रेट द्वारा जिस तारीख को संज्ञान लिया जाता है, उस तारीख को समयपूर्वता देखी जानी चाहिए, जो हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड बनाम एम/एस मानव संसाधन निगम और अन्य के साथ होता है।

1763

(अमन चौधरी, जे.)

लखन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 2013 (3) 752, जिसमें यह मान लिया गया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरसिंह दास तपडिया (उपरोक्त) नामक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए कहा है कि जहां समय से पहले संज्ञान लिया गया था, समय से पहले शिकायत और समय से पहले संज्ञान लेने के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया गया था। इस प्रकार इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामले में चूंकि शिकायत समय से पहले दायर की गई है और चूंकि विचाराधीन अपराध के एक महत्वपूर्ण घटक को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए हाथ में दी गई शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए। ”

पूर्वगामी से यह पता चलता है किः -

तीसरा; प्रत्यर्थी ने वही चेक Ex.D1, जिस पर No.068821 है, जिसे प्रतिभूति के रूप में दिया गया है, लेकिन जिसकी कोई तारीख नहीं है, जिसे उपायुक्त, यमुनानगर के कार्यालय के अधिकारी द्वारा भी साबित किया गया था, जिन्होंने कहा था कि इसका मूल उनके पास उपलब्ध नहीं था, लेकिन फोटोकॉपी उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध थी, जिसे उनके द्वारा सत्यापित किया गया था, यह अपने आप में एक संदेह पैदा करता है और प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए सुरक्षा चेक के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौथा; पक्षों के बीच किए गए समझौते के पैरा 7 के खंड 12 (ii) से यह स्पष्ट है कि प्रतिभूति के अलावा, मिल मालिक/दूसरा पक्ष हाफेड @Rs.25 लाख 1764 के पक्ष में हस्ताक्षरित चेक के रूप में अतिरिक्त गारंटी प्रदान करने के लिए सहमत है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

पाँचवाँ; समझौते के खंड 13 में, यह उल्लेख किया गया था कि यदि मिलर/दूसरा पक्ष अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने या पालन करने में विफल रहता है या लापरवाही करता है, तो उचित अवसर देने के बाद प्रतिभूति को जब्त करना हैफेड/एजेंसी के लिए वैध होगा और राज्य के खजाने को हुए नुकसान की वसूली मिलर/दूसरा पक्ष/प्रतिभूओं से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे मिलर और उनके मिल परिसर को भविष्य के लिए काली सूची में डाला जा सकता है। हालांकि, उपरोक्त खंड में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि अतिरिक्त गारंटी के रूप में हस्ताक्षरित चेक दिनांकित/दिनांकित होने चाहिए थे, या कि चूक या समझौते के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नुकसान की वसूली के लिए उसे प्रस्तुत किया जाएगा, यदि कोई हो, बल्कि खंड में प्रावधान किया गया था कि नुकसान की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी; छठा; चेक 27.9.2010 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसका उसी तारीख को अनादर किया गया था, हालांकि, उस पर कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, वही चेक फिर से < आई. डी. 4>, जिसे फिर से सम तिथि के ज्ञापन के माध्यम से वापस कर दिया गया था, केवल इसके बाद, 20.10.2010 (Ex.C3) दिनांकित कानूनी सूचना 21.10.2010 पर भेजी गई थी। उपरोक्त कानूनी नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने दिनांकित 17.8.2010 (Ex.D4) के पिछले नोटिस में महत्वपूर्ण सुधार किया था, जिसे शिकायतकर्ता-महासंघ द्वारा उत्तरदाताओं को भेजा गया था, जैसा कि डी. डब्ल्यू. 4 जोरा सिंह, अधिवक्ता द्वारा साबित किया गया था, जिसमें पैरा 7 में यह उल्लेख किया गया था कि चेक पर संख्या नहीं है। समझौते के समय प्रतिभूति/गारंटी के रूप में Rs.50,00,000/- की राशि दी गई थी, लेकिन चेक की कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था, और यह कि समझौते के समय जमा की गई FDR और चेक को नुकसान की वसूली के लिए भुनाया जाएगा और उत्तरदाताओं को 10 दिनों के भीतर कार्यालय में शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर संघ को सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करने में बाधा होगी, जबकि, दिनांकित 20.10.2010 (Ex.C3) के कानूनी नोटिस के पैरा 2 में, यह उल्लेख किया गया था कि चेक पर सं. 062281 राशि Rs.50,00,000/- दिनांकित 2.6.2010, मौजूदा देयता के लिए जारी की गई थी; सातवाँ; शिकायतकर्ता कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के घटक को साबित करने के लिए लेखा पुस्तकों को पेश करने में विफल रहा, क्योंकि इस तरह के प्रतिकूल निष्कर्ष उसके खिलाफ निकाले जाने हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह उत्तरदाता ही थे जिन्होंने हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड बनाम एम/एस मानव संसाधन निगम और अन्य के कार्यालय से डी. डब्ल्यू. 2-धारा अधिकारी के माध्यम से उक्त लेखा विवरण प्रस्तुत किए थे।

1765

(अमन चौधरी, जे.)

शिकायतकर्ता स्वयं डी-22 के लिए Ex.D10 के रूप में; आठवाँ; उत्तरदाताओं को धान की आपूर्ति का रिकॉर्ड भी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा कि उसे नहीं पता कि कितना धान की आपूर्ति की गई थी। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने शिकायतकर्ता-अपीलार्थी के कार्यालय के कर्मचारी यानी डी. डब्ल्यू. 2 और डी.-20 के खातों के विवरणों के माध्यम से यह साबित करने के लिए जांच की थी कि चेक में उल्लिखित राशि चेक की तारीख पर उत्तरदाताओं के खिलाफ बकाया नहीं थी, जिससे शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्करण में कमी आती है। नौवां; 6.10.2010 पर चेक का अनादर दिखाने वाला मूल ज्ञापन भी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था और अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया था कि उसके और CW3 के कब्जे में नहीं था, बैंक अधिकारी ने कहा था कि विचाराधीन चेक का कभी भी 6.10.2010 पर अनादर नहीं किया गया था, जो कि चेक रिटर्न रजिस्टर Ex.CW3/A और खातों के विवरण Ex.CW3/B से भी स्पष्ट था। यहां तक कि हस्तलेखन विशेषज्ञ, DW7, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि वापसी ज्ञापन, Ex.C2 पर, तारीख को <ID2 से बदल दिया गया था। आई. डी. 6> यू से 6/10 यू. इसे देखते हुए, 6.10.2010 पर चेक के अपमान का मामला साबित नहीं हुआ और चूंकि शिकायतकर्ता ने कभी भी द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से वापसी ज्ञापन की फोटोकॉपी साबित करने के लिए अदालत से अनुमति नहीं मांगी, इसलिए अधिनियम की धारा 146 के तहत अनुमान लगाने के बावजूद यह साबित नहीं हुआ, जिसका खंडन किया गया था। अंत में, शिकायत 3.11.2010 पर दर्ज की गई थी, यानी कानूनी नोटिस की तारीख से 15 दिन पूरे होने से एक दिन पहले इसे समय से पहले माना गया था।

निष्कर्ष

एम. एस. नारायण मेनन @कई बनाम केरल राज्य और अन्य 2, जहां शिकायतकर्ता द्वारा लेखा पुस्तिका प्रस्तुत नहीं करने के मामले में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के संबंध में मुद्दा और अभियुक्त का रुख यह था कि विचाराधीन चेक प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः -

“37. जी. वासु बनाम सैयद यासीन मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष किसी अनुमान और उसकी प्रकृति का क्या प्रभाव होगा, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

2 2006 (6) एससीसी 39 1766

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

सिफुद्दीन कादरी [ए. आई. आर. 1987 ए. पी. 139]। पूर्ण पीठ की ओर से बोलते हुए, एक निर्देशात्मक निर्णय में, राव, जे. (उस समय उनके स्वामी के रूप में) ने साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ बड़ी संख्या में मामले के कानूनों और अधिकारियों की राय पर ध्यान दियाः "उपरोक्त अधिकारियों से, हम मानते हैं कि एक बार जब प्रतिवादी अदालत की संतुष्टि के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि संभावनाओं की अधिकता पर वाद या वाद नोटिस या वादी के साक्ष्य में अनुरोध किए गए तरीके पर कोई विचार नहीं किया जाता है, तो बोझ वादी पर चला जाता है और धारणा 'गायब' हो जाती है और अब प्रतिवादी को परेशान नहीं करती है। यह आगे आयोजित किया गया थाः "उपर्युक्त कारणों से, हमारा विचार है कि जहां, वचन पत्र पर किसी वाद में, उन परिस्थितियों के बारे में प्रतिवादी का मामला जिसके तहत वचन पत्र निष्पादित किया गया था, स्वीकार नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी के लिए यह साबित करने के लिए खुला है कि वादी द्वारा वचन पत्र में पाठ के आधार पर स्थापित मामला, या वाद नोटिस में या वाद में स्थापित मामला सच नहीं है और धारा 118 के तहत अनुमान का खंडन करते हुए उसके पक्ष में और वादी के खिलाफ संभावनाओं की अधिकता दिखाता है। उसे यह स्थापित करने के लिए विचार के सभी कल्पनीय तरीकों पर साक्ष्य का नेतृत्व करने की आवश्यकता नहीं है कि वचन पत्र किसी भी विचार द्वारा समर्थित नहीं है। धारा 118 में 'जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता' शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से यह दिखाना चाहिए कि दस्तावेज़ किसी भी प्रकार के विचार द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन प्रतिवादी के पास अदालत से विचार के अस्तित्व पर विचार करने के लिए कहने का विकल्प है, जिससे कि मामले की परिस्थितियों में एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि विचार मौजूद नहीं था। यद्यपि साक्ष्य का भार प्रारम्भ में प्रतिवादी पर धारा 118 के आधार पर रखा जाता है, फिर भी प्रतिवादी द्वारा इस बात की संभावनाओं की अधिकता को दर्शाते हुए इसका खंडन किया जा सकता है कि सर्वनाम में, या वाद सूचना में या वाद में बताए गए विचार मौजूद नहीं हैं और एक बार जब अनुमान का इस तरह से खंडन किया जाता है, तो उक्त धारणा 'गायब' हो जाती है। प्रारंभिक साक्ष्य संबंधी बोझ का खंडन करने के उद्देश्य से, प्रतिवादी प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या कानून या तथ्य के अनुमानों पर भरोसा कर सकता है। एक बार जब इस तरह के विश्वसनीय खंडन साक्ष्य को अदालत द्वारा प्रस्तुत और स्वीकार कर लिया जाता है, तो मामले की सभी परिस्थितियों और हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड बनाम एम/एस ह्यूमन राइस मिल और अन्य की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए

1767

(अमन चौधरी, जे.)

संभाव्यताएँ, साक्ष्य का बोझ वादी पर वापस चला जाता है जिसके पास कानूनी बोझ भी होता है। इसके बाद, धारा 118 के तहत अनुमान फिर से वादी के बचाव में नहीं आता है। एक बार जब दोनों पक्ष सबूत पेश कर देते हैं, तो अदालत को उस पर विचार करना पड़ता है और सबूत का बोझ अपना सारा महत्व खो देता है। 38. यदि एक दीवानी मुकदमे के उद्देश्य से, प्रतिवादी उस पर लगाए गए प्रारंभिक बोझ को पूरा करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता है, तो एक 'फोर्टियोरी' यहां तक कि एक आरोपी को भी गवाह बॉक्स में प्रवेश करने और अपने बचाव के समर्थन में अन्य गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसे यह दोहराना होगा कि अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है। ”

(24) हाथ में मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निस्संदेह, शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 138 के तत्वों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा और यह न्यायालय शिकायत में किए गए कथनों को विश्वसनीय बनाने के लिए खुद को कठिन दबाव में पाता है, विशेष रूप से इसकी पुष्टि करने के लिए किसी भी ठोस सबूत के अभाव में और इसे संदेह के तत्वों से घिरा हुआ है, जबकि, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए दावे को हटाने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं, जिसे निचली अदालत द्वारा उचित रूप से सराहा गया।

(25) के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय

P.Mohanraj और अन्य बनाम मेसर्स शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड 3 ने कहा, "इसके अलावा, अधिनियम की धारा 142 (1) (बी) की भाषा इन प्रावधानों की संकर प्रकृति को दर्शाती है क्योंकि धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत" कार्रवाई का कारण "उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए एक विदेशी है। ” यह आगे कहा गया कि "अधिनियम की धारा 144 के तहत, समन की सेवा का तरीका दीवानी मामलों की तरह किया जाता है, धारा 62 से 64 में निहित तरीके को छोड़ते हुए। इसी तरह, धारा 145 के तहत, शिकायतकर्ता द्वारा हलफनामे पर साक्ष्य दिया जाना है, जैसा कि दीवानी कार्यवाही में दिया गया है, हालांकि इसमें कुछ भी शामिल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 147 द्वारा, इस अधिनियम के तहत अपराध अदालत के किसी भी हस्तक्षेप के बिना शमनीय हैं, जैसा कि धारा 320 (2) Cr.P.C द्वारा आवश्यक है। "यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था", एक दीवानी अवमानना कार्यवाही की संकर प्रकृति को देखते हुए, जिसे "अर्ध-आपराधिक" 3 2021 (6) SCC 258 1768 के रूप में वर्णित किया गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के विश्लेषण पर हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए धारा 138 की कार्यवाही पर एक ही आवेदन "अर्ध-आपराधिक" को लागू करने में कुछ भी गलत नहीं है।

(26) इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले में

भविष्य निधि और अन्य 4 ने अभिनिर्धारित किया कि "अधिनियम की धारा 138 में दंडात्मक प्रावधान है। यह एक विशेष क़ानून है। यह प्रत्यावर्ती दायित्व पैदा करता है। यहाँ तक कि कुछ हद तक सबूत का भार भी अभियुक्त पर है। उक्त प्रावधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक गंभीर दंड का प्रावधान करता है, प्रावधान एक सख्त निर्माण की गारंटी देता है। धारा 138 में संलग्न प्रावधान में एक गैर-बाध्यकारी खंड है। इसमें प्रावधान है कि मुख्य प्रावधान में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसमें निर्धारित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है। यह आगे कहा गया था कि खंड (सी) में प्रावधान है कि चेक धारक को उक्त नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन राशि का भुगतान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ” (27) शिकायत की व्यवहार्यता के मुद्दे के संबंध में संबंधित वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों का आकलन करते हुए, इसे 14वें दिन दायर किया गया था और उसी दिन संज्ञान लिया गया था, कानून के तय किए गए प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गजानंद बुरांगे बनाम लक्ष्मी चंद गोयल, 2022 की आपराधिक अपील No.1229 के मामले में दिए गए एक फैसले में स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी। जितेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे और अन्य 5। इस मामले के लिए प्रासंगिक गजानंद बुरांगे (उपरोक्त) के फैसले में प्रासंगिक पारस इस प्रकार हैः

“5. इस अपील में जो मुद्दा उठाया गया है वह अब एकीकृत नहीं है और योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे और एक अन्य (2014) 10 एस. सी. सी. 713 मामले में इस अदालत के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के दायरे में आता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्णय के लिए दो मुद्दे तैयार किए गए थे, जो थेः

“ 1.1. (i) क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान 4 2007 (13) एससीसी 753 हो सकता है?

5 2014 ( 10) एस. सी. सी. 713 हरियाणा राज्य सहयोगात्मक आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड बनाम एम./एस. ह्यूमन राइस मिल और अन्य

1769

(अमन चौधरी, जे.)

उपरोक्त अधिनियम की धारा 138 (सी) के संदर्भ में चेक के दराज को दिए जाने के लिए आवश्यक नोटिस में निर्धारित 15 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत के आधार पर लिया गया? और, 1.2. ((ii) यदि प्रश्न 1 का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या शिकायतकर्ता को इस तथ्य के बावजूद फिर से शिकायत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है कि ऐसी शिकायत दर्ज करने के लिए धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित एक महीने की अवधि समाप्त हो गई है? ”

6. पहले मुद्दे को फैसले के पैराग्राफ 35 द्वारा हल किया गया था, जिसे नीचे निकाला गया हैः

“35. क्या एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कोई अपराध तब किया गया कहा जा सकता है जब परंतुक के खंड (सी) में दी गई अवधि समाप्त नहीं हुई हो? संहिता की धारा 2 (डी) "शिकायत" को परिभाषित करती है। इस परिभाषा के अनुसार, शिकायत का अर्थ है अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से किया गया कोई भी आरोप। शिकायत दर्ज कराने और ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपराध करना अनिवार्य है। परंतुक के खंड (ग) में निहित प्रावधान को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी अपराध के लिए तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि 15 दिनों की अवधि बीत न जाए। दराज़दार/अभियुक्त को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई कोई भी शिकायत कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है। यह शिकायत की समयपूर्वता का सवाल नहीं है जहां उसे नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर किया जाता है, यह कानून के तहत कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में, एन. आई. अधिनियम की धारा 142, अन्य बातों के साथ-साथ, लिखित शिकायत को छोड़कर, धारा 138 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने से अदालत पर कानूनी रोक लगाती है। चूंकि दराज/अभियुक्त को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर की गई शिकायत कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है, इस तरह की शिकायत के आधार पर किसी अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। केवल इसलिए कि 1770 के समय में

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

अदालत द्वारा संज्ञान लेने पर, दराज़दार/अभियुक्त को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, अदालत को चेक के दराज़दार द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत पर धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ” 7. वर्तमान मामले में, जबकि अपीलार्थी को 8 नवंबर 2005 को नोटिस प्राप्त हुआ था, शिकायत पंद्रह दिनों की अवधि पूरी होने से पहले दायर की गई थी। शिकायत 23 नवंबर 2005 के बाद ही दर्ज की जा सकती थी, लेकिन 22 नवंबर 2005 को दर्ज की गई थी। एन. आई. अधिनियम की धारा 142 द्वारा बनाई गई कानूनी रोक को देखते हुए, जैसा कि इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में समझाया गया है, न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना कानून के विपरीत था और शिकायत अपीलार्थी द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले बनाए रखने योग्य नहीं थी। ”

नरसिंह दास तपडिया बनाम गोवर्धन दास परतानी 6 का मामला, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योगेंद्र प्रताप सिंह (उपरोक्त) के मामले में खारिज कर दिया था। प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है; 37. इसलिए हम इसके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं।

नरसिंह दास तपदिया 1 में न्यायालय और इसी तरह नरसिंह के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय भी दास तपडिया1 ने कहा कि यदि धारा 138 के तहत शिकायत उस तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की जाती है जिस दिन दराज/आरोपी को नोटिस दिया गया है, तो वह समय से पहले है और यदि संज्ञान लेने की तारीख को दराज/आरोपी को नोटिस देने की तारीख से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, तो ऐसी शिकायत कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य थी और इसलिए, उसे खारिज कर दिया जाता है।

(29) इस प्रकार, यह देखा गया है कि निचली अदालत ने शिकायत को उचित रूप से बनाए रखने योग्य नहीं माना था, क्योंकि यह पूर्व-परिपक्व होने के कारण, अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान की एक महत्वपूर्ण शर्त को निर्विवाद रूप से पूरा नहीं किया गया था।

6 2000 (7) एस. सी. सी. 183 द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाम एम./एस. ह्यूमन राइस मिल और अन्य

1771

(अमन चौधरी, जे.)

(30) वर्तमान मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद और इस न्यायालय ने जैसा कि पूर्व में निर्दिष्ट किया गया है, प्रचुर निर्णयों के साथ खुद से अनुरोध करने के बाद, इस न्यायालय को वर्तमान मामले में आक्षेपित, निचली अदालत द्वारा पारित सुविचारित निर्णय में कोई अवैधता या विकृति हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। नतीजतन, और इसकी अगली कड़ी के रूप में, आपराधिक अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है। डॉ. पायल मेहता